ग्राम पोंडी में फिर बिजली तार चोरी से हड़कंप

पोल तोड़कर काट ले गए विद्युत तार, पुलिस और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने उठाए गंभीर सवाल

सिवनी जिले की विधानसभा की क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत लगातार दूसरी बड़ी चोरी से दहशत में ग्रामीण और किसान

सिवनी ननभारत। सिवनी। बंडोल विद्युत वितरण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पोंडी में एक बार फिर बिजली तार चोरी की बड़ी घटना सामने आने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। 5 मई 2026 की रात अज्ञात चोरों ने सुनियोजित तरीके से विद्युत लाइन के पोलों को क्षतिग्रस्त कर बिजली के तार काट लिए और मौके से फरार हो गए। सुबह जब ग्रामीणों और किसानों ने बिजली बंद देखी तो मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे किसानों सहित आम ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि चोरों ने जिस प्रकार से पोल तोड़कर तार चोरी किए हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि घटना को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस विभाग बंडोल और विद्युत विभाग को सूचना दे दी गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ना तो चोरी का खुलासा हो पाया है और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती और क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था मजबूत होती, तो संभवत: इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। किसानों का कहना है कि रात के समय अब खेतों और विद्युत लाइनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग केवल औपचारिकताएं निभाते नजर आते हैं। चोरी की घटनाओं के बाद कुछ दिनों तक हलचल दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। यही कारण है कि चोर लगातार सक्रिय बने हुए हैं।किसानों ने बताया कि विद्युत लाइन बार-बार क्षतिग्रस्त होने से खेती-किसानी का कार्य प्रभावित हो रहा है। कई बार बिजली बंद रहने के कारण सिंचाई कार्य रुक जाते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। किसानों का कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।

पिछले वर्ष भी हुई थी चोरी, तब भी नहीं हुआ खुलासा

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पोंडी में विद्युत तार चोरी की यह पहली घटना नहीं है। पिछले वर्ष भी इसी विद्युत लाइन को चोरों ने निशाना बनाया था और बड़ी मात्रा में बिजली के तार चोरी कर लिए गए थे। उस समय भी पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद उस मामले का आज तक खुलासा नहीं हो सका। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण चोरों के हौसले और अधिक बढ़ गए। यदि पहली घटना में ही पुलिस द्वारा आरोपियों तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई की जाती, तो शायद दोबारा ऐसी घटना नहीं होती। लगातार दूसरी बार हुई चोरी ने यह साबित कर दिया है कि क्षेत्र में चोरों को प्रशासन का कोई भय नहीं रह गया है।

बिजली व्यवस्था ठप, किसानों की सिंचाई पर गहराया संकट

बिजली तार चोरी होने के बाद ग्राम पोंडी और आसपास के क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई इलाकों में घंटों तक बिजली बंद रहती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि इस समय खेतों में सिंचाई का कार्य चल रहा है और बिजली आपूर्ति बाधित होने से खेती-किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। कई किसानों की फसलें पानी के अभाव में प्रभावित होने लगी हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय पर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि चोरी के बाद विद्युत व्यवस्था सुधारने में भी विभाग की ओर से तेजी नहीं दिखाई जा रही। कई दिनों तक लाइन सुधार कार्य अधूरा पड़ा रहता है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं।घटना के बाद ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए तथा विद्युत लाइनों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए।

पुलिस और विद्युत विभाग के बीच तालमेल की कमी आई सामने

घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस विभाग बंडोल और विद्युत विभाग के बीच समन्वय की कमी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आते हैं, लेकिन चोरी रोकने और आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस संयुक्त कार्रवाई दिखाई नहीं देती। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा अब तक ऐसा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है जिससे पुलिस विभाग को चोरी का खुलासा करने में सहायता मिल सके। ना तो संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और ना ही विद्युत लाइनों की सुरक्षा के लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनाई गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण चोर लगातार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि विद्युत विभाग और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त रणनीति बनाते, नियमित गश्त कराते और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाते, तो शायद ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही दिए गए। ना तो ग्रामीणों की शिकायतों पर गंभीरता दिखाई गई और ना ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास किया गया। इससे ग्रामीणों का प्रशासन पर से भरोसा कमजोर होता जा रहा है।

नीट प्रकरण : कोचिंग नियंत्रण कानून फाइलों में बंद

75 प्रश हाजिरी नियम भी बना मजाक, 'टाइअप' पर सरकारी सख्ती नहीं

नागपुर, महानगर संवाददाता. देशभर में चर्चित हुए नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद अब निजी कोचिंग संस्थानों की भूमिका और उन पर नियंत्रण को लेकर बहस तेज हो गई है. मामले में बड़े कोचिंग नेटवर्क के नाम सामने आने के बाद यह सवाल फिर उठने लगा है कि आखिर निजी कोचिंग क्लासेस को नियंत्रित करने वाला कानून कब लागू होगा. लातूर के आरसीसी कोचिंग संस्था के संचालक शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी से शहर के कोचिंग क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया है.

कोचिंग संस्थाओं की परीक्षाओं में दखलंदाजी कोई नई बात नहीं है. पिछले दिनों 12वीं स्टेट बोर्ड के 3 विषयों के पेपर लीक हुए थे. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई. जांच में कोचिंग क्लास से ही पेपर लीक होने का खुलासा हुआ था. इस मामले के भी सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके. अभी कुछ पेपर लीक करने वाले बाहर घूम रहे हैं. पूर्व शिक्षा मंत्री विनोद तावडे के कार्यकाल में निजी कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. उस समय एक प्रारूप भी तैयार किया गया था लेकिन वह कानून अमल में नहीं आ सका. इसके बाद भी राज्य शिक्षा विभाग ने कोचिंग क्लासेस पर नियंत्रण के लिए मसौदा तैयार किया, मगर उसे आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी है.

- केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी बेअसर

केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे. इनमें विद्यार्थियों पर अत्यधिक दबाव, भ्रामक विज्ञापन, अत्यधिक फीस और अनियमित शैक्षणिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की बात कही गई थी. हालांकि जमीनी स्तर पर इन नियमों का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है.

- 75 प्रतिशत उपस्थिति नियम पर सवाल

राज्य बोर्ड के नियमों के अनुसार 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल या कॉलेज में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. इतनी उपस्थिति होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है. यदि कोई छात्र बीमार है या अन्य किसी कारण से 75 फीसदी उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता तो उसे ठोस कारण देना अनिवार्य होता है. लेकिन 'इंटीग्रेटेड' और 'टाइअप' मॉडल के जरिए कई विद्यार्थी वास्तविक रूप से कॉलेज में उपस्थित हुए बिना केवल कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं. इस व्यवस्था में कुछ कोचिंग संस्थान कनिष्ठ महाविद्यालयों (जूनियर कॉलेज) के साथ समझौता कर विद्यार्थियों का प्रवेश वहां दिखाते हैं, जबकि पढ़ाई पूरी तरह कोचिंग सेंटर में कराई जाती है. कॉलेजों में केवल औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराई जाती है.

- बायोमेट्रिक उपस्थिति दिखावे की

सरकार ने स्कूलों, जूनियर कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया है. हालांकि कुछ अनुदानित महाविद्यालयों में उपस्थिति की सख्ती की जाती है लेकिन अधिकांश जगह नहीं होती. जब छात्र जूनियर कॉलेज की बजाय कोचिंग में जाएंगे तब उपस्थिति कैसे दर्ज होगी. कई जूनियर कॉलेजों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए बाकायदा कर्मचारी नियुक्ति किए हैं जो छात्रों की फर्जी उपस्थिति लगाते हैं.

एक नजर में

पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के लिए शाला में नवाचार

बोरीकला। बरघाट विकासखंड के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बोरी कला में इन दोनों नवाचार के रूप में मां की बगिया के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को प्रेरित करने के लिए छोटी सी जगह में पौधे लगाने का काम किया जा रहा है इसका उद्देश्य है कि बच्चे प्रेरित हो और साल के साथ-साथ अपने घरों में भी पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संवर्धन संरक्षण के लिए प्रेरित हो और लोगों को भी जागरूक करें इस कार्य में प्राचार्य एस के बाहने श्री उईके सहित समस्त स्टाफ का योगदान मिल रहा है प्राचार्य श्री बाहने ने कहां है कि यह छोटे-छोटे से नवाचार हमें पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करते हैं अगर बचपन से ही लोग पर्यावरण के महत्व को समझेंगे जानेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हम पर्यावरण के आने वाले खतरे से बच सकते हैं इस छोटी सी बगिया के माध्यम से हम जल संवर्धन जल संरक्षण का कार्य भी कर सकते हैं।

रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ऐंठे 39 लाख

सिवनी कोतवाली पुलिस ने ग्लोबल मार्केटिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 39 लाख 29 हजार रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 60 लाख की बीएमडब्ल्यू कार और महंगे मोबाइल सहित करीब 62 लाख रुपये की संपत्ति जप्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में नितिन सोनी और ललित पुरोहित शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने निवेश पर कम समय में दोगुना मुनाफा देने का लालच देकर लोगों से रकम ऐंठी थी। थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ठगी करना स्वीकार किया है। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है।

सुनवाई में बागरी समाज का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र व अशोक

सिवनी। जिले में बघेल बागड़ी समाज से जुड़े प्रमाण पत्र मामले को लेकर समाज में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर भोपाल हाईकोर्ट में 20 मई को होने वाली सुनवाई में समाज की ओर से मजबूत पक्ष रखने हेतु वरिष्ठ समाजसेवी सुरेंद्र बारमाटे एवं अशोक डेहरिया भोपाल पहुंचे हैं। समाजजनों से इस सामाजिक लड़ाई में एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की गई है। समाज का कहना है कि सत्य, न्याय और सम्मान की रक्षा के लिए सभी का साथ जरूरी है।

6 महीनों से नहीं मिला वेतन, आर्थिक संकट में पानी एवं स्वच्छता विभाग के 1,000 कर्मचारी

नागपुर, निज संवाददाता. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने वाली जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत लगभग 1,000 संविदा कर्मचारियों पर शासन की लापरवाही के कारण गंभीर आर्थिक संकट आ गया है. राज्य की 34 जिला परिषदों में जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है जिसके चलते तीव्र नाराजगी व्यक्त की जा रही है. कर्मचारियों को आर्थिक तंगी के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. मानसिक रूप से भी त्रस्त हो गए हैं. जल जीवन मिशन के कर्मचारियों का जहां 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया वहीं स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों का मानधन 4 महीनों से लंबित है. कृति समिति के अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड़ ने कहा कि ठेकेदारों का नियमित भुगतान किया जा रहा है लेकिन कर्मचारियों को ताक पर रख दिया गया है. इससे सरकार की प्राथमिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

मैट के आदेश का उल्लंघन

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मैट) की औरंगाबाद खंडपीठ ने 12 फरवरी 2026 को लंबित वेतन और अन्य देयकों का तत्काल भुगतान करने के स्पष्ट आदेश दिए थे. इसके अलावा मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए शासन को नोटिस जारी किया है. इसके बावजूद आदेशों का पालन न होने से सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त हो रहा है. विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल 2026 तक का वेतन दिया जा चुका है, जबकि संविदा कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से न तो मानदेय मिला है .

केवलारी में घंटो तक लग रहा मुख्य सड़क पर जाम, पैदल चलना भी मुश्किल

केवलारी नवभारत। केवलारी नगर कहने को तो ग्रामपंचायत का चोला निकालकर नगरपरिषद हो चुका है परंतु नगर के हालात और व्यवस्था सुधारने के लिए निर्वाचित पदाधिकारियों की सोच कहीं से नजर नही आती। नगरपरिषद बनने के बाद शासन से प्राप्त राशि से संसाधनों की बेहिसाब खरीद फरोख्त तो कर ली गयी लेकिन उनके रखरखाव और संचालन की कोई ठोश योजना पर काम नही किया गया जिससे लोगों को महसूस होने लगा है जैसे नगरपरिषद की मांग उठाकर यहां के लोगों ने कोई भारी भूल कर ली हो।

नगर की मूलभूत सुविधाओं के अलावा यातायात और सुगम सड़क मार्ग पर आवागमन की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी नगरपरिषद की है जिसे लेकर जिम्मेदार कहीं से गंभीर नजर नही आते।

नगर में यातायात व्यवस्था इतनी बेहाल है कि लगभग हर दिन ही मुख्यसडक पर जाम की स्तिथि निर्मित होती है जिसमे फंसकर आनेजाने वाले लोग व्यवस्था को कोसते नजर आते हैं।यात्री बसों के ख ? होने के लिए विशाल परिषर में बसस्टैंड बना है जिसमे एक वक्त पर आधा दर्जन बस खड़ी की जा सकती हैं फिर भी इस मार्ग पर चलने वाली अधिकतर बस सड़क में ही खड़ी की जाती हैं जिससे अन्य वाहनों को निकलने का रास्ता नही मिलता और बसों के पीछे अन्य वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है। इतना ही नही अधिकतर बसें स्टैंड से निकल कर ऊगली नाका और अस्पताल के सामने आकर सड़क पर काफी देर तक खड़ी की जाती हैं जिससे अक्सर ही जाम की स्तिथि निर्मित होती है।सुक्रवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार के दिन तो स्थिति विकराल हो जाती है जब अस्थायी दुकानों की बजह से मुख्यसडक पर घंटो तक जाम लग जाता है।जिस वजह से लंबी दूरी के यात्रियों को गन्तव्य तक पहुंचने में विलंब होता है।

ऊगली नाका से लेकर अस्पताल के सामने तक सड़क मार्ग पर स्थित दुकानों में दुकानदारों ने बाहर तक अपना सामान फैला कर रखा है साथ ही सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों ने सड़क के किनारे से ही दुकाने लगा रखी हैं।

बैंकों में नही है पार्किंग व्यवस्था

बसस्टैंड में स्थित सेंट्रल बैंक और अस्पताल के सामने स्थित स्टेट बैंक जो कि सड़क से लग कर हैं उनके सामने पार्किंग की कोई व्यवस्था नही है जिससे वहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले ग्राहकों के दुपहिया वाहन सड़क पर खड़े किए जाते हैं इससे मुख्यसडक पर वाहनों की आवाजाही के लिए भारी मुश्किल पैदा हो जाती है।

शांति समिति की बैठक में एसपी ने दिए निर्देश : ईदुज्जुहा, उर्स, महाराणा प्रताप जयंती व मोहर्रम पर रहेगी विशेष व्यवस्था

आगामी पर्वों के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु शांति समिति की बैठक संपन्न

सिवनी नवभारत। आगामी धार्मिक पर्वों एवं आयोजनों को सौहार्दपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस कंट्रोल रूम सिवनी में जिला शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी (भा.पु.से.) द्वारा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, समस्त एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी, शांति समिति के सदस्य, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में 27 मई ईदुज्जुहा (बकरीद), 21 से 23 मई उर्स आयोजन एवं संदल कार्यक्रम, 17 जून महाराणा प्रताप जयंती, 26 जून मोहर्रम को लेकर चर्चा हुई। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि सिवनी जिले में सभी धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होना हमारी गौरवशाली परंपरा है। उन्होंने निर्देश दिए कि नगरपालिका मस्जिदों, ईदगाहों एवं आयोजन स्थलों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं कचरे का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करे। पेयजल एवं विद्युत विभाग पर्वों के दौरान निर्बाध आपूर्ति बनाए रखें। यातायात पुलिस भीड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यक बैरिकेडिंग एवं रूट डायवर्सन की व्यवस्था करे। स्वास्थ्य विभाग आयोजन स्थलों पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करे। सभी विभागों में समन्वय रहे तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने सभी समुदायों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी केवल निर्धारित एवं बंद परिसर में ही की जाए। खुले या सार्वजनिक स्थल पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। ईदगाहों में नमाज के दौरान व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त वॉलिंटियर्स की तैनाती की जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें अग्रेषित करें। संदिग्ध/भ्रामक जानकारी तत्काल पुलिस को दें। साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया की 24×7 मॉनिटरिंग की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी। सभी पर्वों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा एवं ड्रोन/सीसीटीवी से सतत निगरानी की जाएगी।

प्रभारी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी धर्मावलंबियों एवं समिति सदस्यों से प्रशासन का सहयोग करने तथा जिले की सामाजिक सौहार्द की परंपरा को बनाए रखने की अपील की। बैठक में उपस्थित सभी धर्मगुरुओं एवं शांति समिति सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए आगामी सभी पर्वों को शांतिपूर्ण एवं उल्लास के साथ मनाने का संकल्प व्यक्त किया।

सौगात | राज राजेश्वरी चौक एवं महाराणा प्रताप चौक तक डिवाईडर युक्त सडक का होगा निर्माण कार्य

बरघाट नगर की बहुप्रतिक्षित मांग डिवाईडर युक्त सड़क का कार्य प्रारंभ

बरघाट नवभारत। नगर बरघाट की जनता की बहुप्रतिक्षित मांग जिसका नगर की जनता को बेसबीं से इंतजार था उस डिवाईडर युक्त सड़क निर्माण कार्य का आज मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (चतुर्थ चरण) एवं माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत नगर सीमा के भीतर राज राजेश्वरी चौक एवं महाराणा प्रताप चौक तक डिवाईडर युक्त सडक निर्माण कार्य कराया जाना है।

नगर बरघाट की सीमा से गुजरने वाले सिवनी - बालाघाट मार्ग जो नगर ब्लाक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय होने के साथ जिसमें अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र है। सम्पूर्ण मुख्य मार्ग में अनेकों शासकीय, अशासकीय कार्यालय/संस्थान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान होने से जिस पर पूरे समय यातायात का अत्याधिक दबाव बना रहता है, जिसे दुर्घटना मुक्त करने के साथ क्षेत्र की सुरक्षा की ओर विकास का बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

नगर बरघाट की जनता जिस कार्य के प्रारंभ होने का कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। आवश्यक दस्तावेजों एवं शासकीय प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए आज डिवाईडर युक्त सड़क का निर्माण कार्य नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता अनिल पाठक, सभापति हेमंत राहंगडाले, सभापति श्रीमती निधि ऋषभ जायसवाल, सभापति असंत उइके, पार्षद व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती संध्या अनिल सिंह ठाकुर, पूर्व पार्षद अनिल पाठक एवं नगर परिषद के अमले की उपस्थिति में सदगुरु शिवालय के सामने से प्रारंभ कराया गया।

प्रथम चरण का काम शुरू

उल्लेखनीय लेख है कि नगर सीमा में डिवाईडर युक्त सड़क निर्माण कार्य उत्कृष्ट विद्यालय से श्याम पेट्रोल पंप तक कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य राज राजेश्वरी चौक एवं महाराणा प्रताप चौक तक किया जावेगा। उक्त कार्य की लागत राशि 321.13 लाख रू. है जिसे संविदाकार दादागुरू कन्स्ट्रक्शन, सिवनी के द्वारा 06 माह की समयावधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा ।

तेंदूपत्ता तोडने गये युवक का बाघ ने किया शिकार

धारनाकला नवभारत। बरघाट विकास खंड के अन्तर्गत चमरवाही के जंगल मे आज फिर एक दर्दनाक घटना सामने आई है और इस दर्द नाक घटना ने फिर एक बार लोगो को झकझोर कर रख दिया है

आज सबेरे चमरवाही ग्राम का नवयुवक इन्द्र कुमार परते अन्य दिनो की तरह जंगल मे तेंदूपत्ता तोडने के लिये निकला था तेंदूपत्ता तोडते तोडते जंगल के काफी अन्दर जाने के बाद और बहुत देरी तक कोई आहट न मिल पाने के चलते अगर साथियो ने तलाश की तब तक बाघ के द्वारा इन्द्र कुमार परते का बाघ के द्वारा शिकार किया जा चुका था बाघ के द्वारा शरीर के निचले हिस्से को बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया कर दिया गया सूचना आग की तरह छेत्र मे फैल गई और चमरवाही से लगे अन्य ग्रामो के लोग भी घटना की खबर सुनकर जंगल की ओर निकल पडे

इसके साथ ही हमेशा की तरह घटना स्थल पर विजय उईके जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य लकी अमूले ने मौके पर पहूचकर परिवार के सदस्यो के साथ खडे होने का दायित्व निभाने मे कोई कसर नही छोडी

उल्लेखनीय है की घटना को लेकर भारी आक्रोश सामने आया स्थल पर वन विभाग से भारी तादाद मे एकत्रित ग्रामीण जनो ने तत्काल मुआवजे की मांग करते हुऐ मृतक की बाडी को रोके रखा गया वन विभाग द्वारा तत्काल 17 लाख रूपये का प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजा गया है तथा यह भी आश्वासित किया गया है यह राशि एक सप्ताह के अन्दर परिवार के खाते मे आ जायेगी आक्रोश को देखते हुऐ वन विभाग के साथ साथ थाना प्रभारी बरघाट मोहनीश बैस भी अपने सदल बल के साथ स्थल पर बने रहे तथा आक्रोशित समुदाय को समझाई स देते नजर आये यहा यह बताना भी लाजिमी है की बाघ के शिकार की यह पांचवी घटना घटित हो चुकी है इसके पूर्व भी घटित घटना के सम्बन्ध मे भारी आक्रोश सामने आया था।